Committee for the Implementation of MPLADS

706. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the present stage of the implementation of Government's promise to set up a committee of MPs to oversee the implementation of the MPLADS;

(b) what is the reason for the delay in constituting such a committee;

(c) what is Government's plans in finalising the structure and organisation of this committee; and

(d) have Government studied the EGS Committee of Maharashtra in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA): (a) to (c) The question regarding the setting up of a Joint Committee of both Houses of Parliament to look into the scheme from time to time on the lines of the Employment Guarantee Scheme Committee of the Maharashtra Legislature was discussed while answering Starred Question No. 106 on 7.8.95. The Government had indicated *inter alia* that it was too early to set up such a Committee as the scheme was in its initial stages. The proceedings of the House indicate that no final decision in the matter was taken.

(d) The Government are aware of the objectives as well as the role of the Employment Guarantee Scheme Committee of the Maharashtra Legislature.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) और राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) द्वारा यूरिया के आयात के लिये निविदाएं

707. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के आयात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) और राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) द्वारा विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994 और 1995 के दौरान आज तक का अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितना यूरिया आयात किया जाना है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(घ) क्या सबसे कम बोली देने वाले को जिसने निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया है; ठेका नहीं दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इन संगठनों में ऐसी सभी अनियमितताओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के आयात के बारे में एक विवरण पत्र सभापटल पर रख दिया गया है **(नीचे देखिए)**

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यूरिया का अनुमान, अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिनमें वर्षा तथा घरेलू आपूर्तियों की उपलब्धता इत्यादि शामिल हैं। इसकी मात्रा के बारे में बताना अभी संभव नहीं है।

(घ) से (च) एम एम टी सी और एस टी सी दोनों ही सामान्यतः सबसे कम बोली लगाने वाले उन लोगों को ही ठेके देते हैं जो सभी निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं। फिर भी ऐसे दुर्लभ अपवाद हो सकते हैं, जहां निर्धारित कीमतों पर, समय पर, सुपुर्दगी करने के बारे में विदेशी आपूर्तिकर्त्ता की विश्वसनीयता संदेहजनक हो।